रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99

REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13102023-249377
CG-DL-E-13102023-249377

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4287] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 12, 2023/आश्विन 20, 1945
No. 4287] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 12, 2023/ASVINA 20, 1945

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 अक्तूबर, 2023

का.आ. 4458(अ).—विभिन्न पणधारकों के पर्यावरण अनुकूल कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिए ग्रीन क्रेडिट हेतु बाजार-आधारित दृष्टिकोण का लाभ उठाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम आरंभ किया जा रहा है;

और भारत सरकार ने पर्यावरण की सुरक्षा एवं संरक्षण और पर्यावरण अनुकूल कार्यों, जो संरक्षण एवं संयम की परंपराओं एवं मूल्यों पर आधारित जीवन जीने के स्वस्थ एवं सतत तरीके का प्रचार करते हों, को बढ़ाकर अन्य पर्यावरणीय एवं जलवायु लाभों के लिए और सतत एव पर्यावरण हितैषी विकास के लिए भू स्तर पर, जन आंदोलन के रूप में 'लाइफ' - 'पर्यावरण हेतु जीवन शैली' का प्रारम्भ है;

और पर्यावरण के प्रति सकारात्मक कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिए बाजार-आधारित अभिनव तंत्र "लाइफ" आंदोलन को बढ़ावा देने में सहायता करेगा, जिसका उद्देश्य उपभोक्ताओं और समाज को पर्यावरण अनुकूल कार्यों को बढ़ावा देने वाले व्यवहारिक परिवर्तनों की ओर प्रेरित करके सतत जीवन शैली को प्रोत्साहित करना है;

और ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) के अधीन बनाई गई कार्बन क्रेडिट व्यापार स्कीम, 2023 से पृथक है, ग्रीन क्रेडिट प्रदान करने वाले पर्यावरणीय कार्यों से जलवायु संबंधी लाभ भी हो सकते हैं, जैसे कार्बन उत्सर्जन को कम करना या समाप्त करना और ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम के अधीन ग्रीन क्रेडिट प्रदान करने वाला कार्य, उक्त स्कीम के अधीन उसी कार्य के लिए कार्बन क्रेडिट भी प्राप्त किया जा सकेगा;

और ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम कार्यान्वयन नियम, 2023 का प्रारूप भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में अधिसूचना संख्या का.आ. 2779 (अ), तारीख 26 जून, 2023 द्वारा प्रकाशित किया गया था जिसमें सभी व्यक्तियों से आपत्तियाँ और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और केंद्रीय सरकार द्वारा प्राप्त सभी आपत्तियों और सुझावों पर सम्यक रूप से विचार किया गया है;

अतः अब, केंद्रीय सरकार पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29), धारा 3, धारा 6 और धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्: -

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** — (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम ग्रीन क्रेडिट नियम, 2023 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम के उद्देश्य.** - (1) ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम बाजार-आधारित तंत्र के माध्यम से पर्यावरण हेतु सकारात्मक कार्यों को प्रोत्साहित करेगा और ग्रीन क्रेडिट प्रदान करेगा, जिससे व्यापार कर पाएंगे और ये घरेलू बाजार मंच पर व्यापार हेतु उपलब्ध कराए जाएंगे।

(2) ग्रीन क्रेडिट नियम 4 के उप-नियम (2) में निर्दिष्ट किसी भी पर्यावरणीय कार्य के लिए किसी व्यक्ति द्वारा किए गए उपाय से प्राप्त होगा।

(3) ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम उद्योगों, कंपनियों और अन्य संस्थाओं को वर्तमान में प्रवृत्त किसी भी विधि के अंतर्गत विद्यमान दायित्वों या अन्य दायित्वों को पूरा करने के साथ-साथ नियम 4 में निर्दिष्ट स्वैच्छिक पर्यावरणीय उपाय करने हेतु अन्य व्यक्तियों, और इकाइयों को सुविधा प्रदान करने के लिए ग्रीन क्रेडिट प्रदान कर या खरीदकर प्रोत्साहित करेगा;

परन्तु कि उस समय प्रवृत्त विधि की अनुपालना में पूरे किए गए दायित्व से सृजित या प्राप्त ग्रीन क्रेडिट व्यापार योग्य नहीं होगा।

3. **परिभाषाएँ** - (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(क) "प्रशासक" से नियम 7 में निर्दिष्ट प्रशासक अभिप्रेत है;

(ख) "अभिहित अभिकरण" से नियम 13 के अधीन ऐसी अभिहित कोई इकाई अभिप्रेत है;

(ग) "ग्रीन क्रेडिट" से किसी विशिष्ट कार्य, जिसका पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता हो, हेतु प्रदान किए गए प्रोत्साहन की एकल इकाई अभिप्रेत है;

(घ) "रजिस्ट्री" से तात्पर्य नियम 10 के अधीन स्थापित ग्रीन क्रेडिट रजिस्ट्री अभिप्रेत है।

(2) उन शब्दों और पदों के जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किंतु पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में है।

4. **ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम** - (1) कोई व्यक्ति या इकाई पर्यावरण की सुरक्षा, परिरक्षण या संरक्षण के प्रयोजनार्थ उप-नियम (2) में निर्दिष्ट कोई भी उपाय कर सकेगा।

(2) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट उपायों में निम्नलिखित कार्य सम्मिलित हैं, अर्थात्:-

(i) वृक्षारोपण – सम्पूर्ण देश में हरित आवरण बढ़ाने के लिए कार्यों को प्रोत्साहन हेतु;

(ii) जल प्रबंधन - जल संरक्षण, जल संचयन और जल के कुशल उपयोग या जल बचत को प्रोत्साहन हेतु, जिसमें अपशिष्ट जल का उपचार और पुनः उपयोग सम्मिलित है;

(iii) सतत कृषि - उत्पादकता, मृदा स्वास्थ्य और उत्पादित खाद्य के पोषण मूल्य में सुधार लाने हेतु प्राकृतिक एवं पुनर्योजी कृषि प्रथाओं और भूमि पुनरूद्धार को प्रोत्साहन हेतु;

(iv) अपशिष्ट प्रबंधन - संग्रहण, पृथक्करण और पर्यावरण की दृष्टि से सुदृढ़ प्रबंधन सहित अपशिष्ट प्रबंधन हेतु चक्रीयता, सततता और परिष्कृत प्रथाओं को प्रोत्साहन हेतु;

(v) वायु प्रदूषण में कमी लाना - वायु प्रदूषण में कमी लाने वाले उपायों और अन्य प्रदूषण उपशमन कार्यकलापों के प्रोत्साहन हेतु;

(vi) मैंग्रोव संरक्षण और पुनरूद्धार - मैंग्रोव के संरक्षण और पुनरूद्धार के उपायों को प्रोत्साहन हेतु;

(vi) इकोमार्क लेबल विकसित करना - विनिर्माताओं को अपने माल और सेवाओं हेतु इकोमार्क लेबल प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना;

(vii) सतत भवन और बुनियादी ढांचा - पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकियों और सामग्रियों का उपयोग करके सतत भवनों एवं अन्य आधारभूत ढांचे के निर्माण को प्रोत्साहित करना।

(3) ग्रीन क्रेडिट प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति या संस्था को उप-नियम (2) में निर्दिष्ट किसी भी कार्य हेतु ग्रीन क्रेडिट लेने के लिए उनके द्वारा किए गए कार्य को प्रशासक के पास रजिस्टर करना होगा।

(4) उप-नियम (3) के अधीन रजिस्ट्रीकरण हेतु आवेदन केंद्रीय सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ स्थापित वेबसाइट के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रशासक को किया जाएगा।

(5) उप-नियम (4) के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर, प्रशासक कार्य को किसी अभिहित अभिकरण द्वारा सत्यापित कराएगा।

(6) अभिहित अभिकरण, इस संबंध में बनाए गए दिशानिर्देशों के अनुसार, सत्यापन एवं पूछताछ, यथावश्यक, के पश्चात, आवेदक द्वारा किए गए कार्यों की पुष्टि करते हुए प्रशासक को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(7) आवेदक द्वारा किए गए कार्यों की पुष्टि करते हुए उप-नियम (6) के अधीन रिपोर्ट प्राप्त होने पर, प्रशासक आवेदक को ग्रीन क्रेडिट का प्रमाण पत्र प्रदान करेगा।

5. ग्रीन क्रेडिट उत्पन्न करने की पद्धति - (1) किसी भी कार्य के संदर्भ में ग्रीन क्रेडिट की गणना करने की पद्धति इस प्रकार होगी, जो प्रशासक की सिफारिशों पर केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए।

(2) किए गए किसी भी कार्य के संदर्भ में ग्रीन क्रेडिट की गणना वांछित पर्यावरणीय परिणाम प्राप्त करने हेतु आवश्यक संसाधन, समान स्केल, क्षेत्र, आकार एवं अन्य प्रासंगिक मापदंडों की समकक्षता पर आधारित होगी।

(3) नियम (4) के अधीन निर्दिष्ट कार्यों हेतु ग्रीन क्रेडिट उत्पन्न करने और जारी करने की पद्धतियाँ केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाएंगी।

6. ग्रीन क्रेडिट उत्पन्न करने की प्रक्रिया - (1) ग्रीन क्रेडिट की गणना के प्रयोजनार्थ किए गए कार्यों के मूल्यांकन और सत्यापन की पद्धति इस प्रकार होगी, जो प्रशासक द्वारा निर्धारित की जाए।

(2) कार्यों के रजिस्ट्रीकरण का तरीका और इस प्रकार के रजिस्ट्रीकरण हेतु अपेक्षित विवरण प्रशासक द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

(3) प्रशासक कार्यों के रजिस्ट्रीकरण, किए गए कार्यों के मूल्यांकन एवं सत्यापन और इस प्रकार सत्यापित कार्यों के के संबंध में इलेक्ट्रॉनिक रूप से ग्रीन क्रेडिट प्रदान करने हेतु वेबसाइट विकसित करेगा।

7. प्रशासक - (1) भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद, सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 का सं. 21 के अधीन रजिस्ट्रीकरण संख्या 596/1990-91 के अधीन रजिस्ट्रीकरण सोसायटी तारीख 12 मार्च, 1991 द्वारा स्थापित और तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा फा. सं.1-8/89-आरटी, तारीख 22 जून, 1990 के माध्यम से यथाघोषित एक स्वायत्त निकाय, इन नियमों के अधीन प्रशासक होगा।

(2) प्रशासक इन नियमों के अधीन इसके प्रबंधन और संचालन सहित ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी होगा।

(3) प्रशासक के उत्तरदायित्वों में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे, अर्थात्: -

(क) इन नियमों के अधीन ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देश, प्रक्रियाएं और कार्य प्रणाली विकसित करना;

(ख) पद्धतियां, रजिस्ट्रीकरण प्रक्रिया, दिशानिर्देश और संबंधित माप, रिपोर्टिंग और सत्यापन हेतु तंत्र विकसित करना;

(ग) ग्रीन क्रेडिट (डिजिटल ग्रीन क्रेडिट जारी करने सहित) और प्रत्येक चिह्नित कार्य से उत्पन्न ग्रीन क्रेडिट का समतुल्य जारी करने हेतु कार्यप्रणाली और प्रक्रियाएं स्थापित करना;

(घ) ग्रीन क्रेडिट रजिस्ट्री और व्यापार मंच की स्थापना और संचालन हेतु; ग्रीन क्रेडिट जारी करने हेतु किसी कार्य के रजिस्ट्रीकरण के लिए स्व-प्रमाणन या तृतीय पक्ष प्रमाणन हेतु; अभिहित अभिकरण द्वारा इसके निरीक्षण और सत्यापन हेतु और लेखा-परीक्षकों का पैनल बनाने एवं ऐसे लेखा-परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षा करने हेतु दिशानिर्देश विकसित करना;

(ङ) अनुमोदित दिशानिर्देशों के अनुसार ग्रीन क्रेडिट रजिस्ट्री व्यापार मंच सेवा प्रदाता की स्थापना या नामित करना;

(च) ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम पोर्टल, ज्ञान एवं डेटा मंच और रजिस्ट्रीकरण संस्थाओं से शुल्क के लिए दिशानिर्देश विकसित करना;

(छ) नामित अभिकरण, रजिस्ट्री, व्यापार मंच और ज्ञान एवं डेटा मंच द्वारा वार्षिक विवरणियां एवं प्रगति प्रतिवेदन दर्ज करने के लिए दिशानिर्देश विकसित करना;

(ज) ग्रीन क्रेडिट के व्यापार हेतु बाजार स्थिरता तंत्र के लिए दिशानिर्देश विकसित करना।

(झ) ग्रीन क्रेडिट प्रमाणपत्रों के व्यापार से संबंधित मामलों को विनियमित करना और विक्रेताओं और क्रेताओं दोनों के हितों की रक्षा करना और धोखाधड़ी या अविश्वास को रोकने के लिए निवारक एवं सुधारात्मक कार्रवाई करना।

(4) प्रशासक उपरोक्त उपनियम (3) के अधीन दिशानिर्देशों एवं पद्धतियों हेतु केंद्रीय सरकार का अनुमोदन प्राप्त करेगा।

8. संचालन समिति - (1) केंद्रीय सरकार द्वारा गठित की जाने वाली संचालन समिति इन नियमों के अधीन ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम के कार्यान्वयन की निगरानी हेतु उत्तरदायी होगी।

(2) संचालन समिति में मंत्रालयों या विभागों के प्रतिनिधि, पर्यावरण क्षेत्र के विशेषज्ञ, उद्योग संघ और अन्य प्रासंगिक पणधारक सम्मिलित होंगे जिन्हें केंद्रीय सरकार उचित समझे।

(3) संचालन समिति, समय-समय पर, इन नियमों के अधीन ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम की समीक्षा करेगी और निम्नलिखित के संबंध में केंद्रीय सरकार को सिफारिशें करेगी, अर्थात्:-

(क) ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम में सम्मिलित किए जाने वाले कार्य और क्षेत्र के संबंध में; और

(ख) केंद्रीय सरकार द्वारा इसको संदर्भित किसी भी मामले के संदर्भ में।

9. तकनीकी समिति — (1) केंद्रीय सरकार, प्रशासक की सिफ़ारिशों के आधार पर प्रत्येक कार्य हेतु तकनीकी समितियों का गठन कर सकेंगी, जो इन नियमों के अधीन ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम के कार्यान्वयन में प्रशासक की सहायता करेगी।

(2) प्रत्येक तकनीकी समिति के सदस्यों में मंत्रालयों एवं विभागों, संगठनों और उस कार्य से संबंधित क्षेत्र में ज्ञान और अनुभव रखने वाले विशेषज्ञ सम्मिलित होंगे;

(3) तकनीकी समिति सिफारिशें विकसित करेगी और प्रशासक को प्रेषित करेगी जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित सम्मिलित भी होगा –

(क) वांछित पर्यावरणीय परिणाम प्राप्त करने हेतु आवश्यक संसाधन, समान स्केल, क्षेत्र, आकार एवं अन्य प्रासंगिक मापदंडों की समकक्षता के आधार पर ग्रीन क्रेडिट की एक इकाई की गणना के लिए पद्धति;

(ख) प्रत्येक कार्य के संबंध में रजिस्ट्रीकरण, सत्यापन, मूल्यांकन, माप और रिपोर्टिंग प्रक्रिया के लिए तंत्र।

(4) प्रशासक द्वारा तकनीकी समिति को निर्दिष्ट किसी भी अन्य तकनीकी मामले पर यह परामर्श देगी।

10. ग्रीन क्रेडिट रजिस्ट्री - (1) प्रशासक या नामित अभिकरण प्रत्येक ग्रीन क्रेडिट का रजिस्ट्रीकरण करने एवं जारी करने हेतु ग्रीन क्रेडिट रजिस्ट्री की स्थापना एवं रखरखाव करेगी।

(2) रजिस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस होगी, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, रजिस्ट्रीकरण एवं ग्रीन क्रेडिट जारी करने से संबंधित सामान्य डेटा तत्व सम्मिलित होंगे।

(3) रजिस्ट्री निम्नलिखित कार्यों का निर्वहन करेगी, अर्थात्: -

(क) कार्यों का रजिस्ट्रीकरण और ग्रीन क्रेडिट जारी करना;

(ख) ग्रीन क्रेडिट जारी करने का सटीक लेखा-जोखा सुनिश्चित करना;

(ग) सभी आवश्यक एवं अनिवार्य सुरक्षा प्रोटोकॉल के साथ सुरक्षित डेटाबेस बनाए रखना;

(घ) प्रशासक द्वारा इसे सौंपा गया कोई अन्य कार्य।

11. ट्रेडिंग प्लेटफार्म - (1) प्रशासक केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से (व्यापार मंच) ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की स्थापना करेगा एवं उसका रखरखाव करेगा।

(2) ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से प्रशासक द्वारा बनाए गए दिशानिर्देशों के अनुसार, ग्रीन क्रेडिट के व्यापार संबंधी कार्य करेगा।

12. ज्ञान एवं डेटा मंच - (1) प्रशासक किए जा रहे विभिन्न कार्यों के संबंध में पारदर्शिता प्रदान करने और इन नियमों के अधीन क्षेत्रवार प्रगति की रिपोर्ट करने हेतु, केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से, ज्ञान एवं डेटा मंच विकसित करेगा एवं उसका रखरखाव करेगा।

(2) ज्ञान एवं डेटा मंच रजिस्ट्री से उत्पन्न प्रमुख डेटा बिंदुओं और अन्य जानकारी, जैसे क्षेत्रवार उपलब्धियां, सर्वोत्तम प्रथाएं, क्षमता निर्माण संबंधी जानकारी आदि को संगृहीत कर सकेगा।

13. अभिहित अभिकरण - (1) प्रशासक ऐसी संस्थाओं को केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित दिशानिर्देशों के अनुसार अभिहित अभिकरण के रूप में कार्य करने के लिए संस्थाओं को नामित करेगा।

(2) अभिहित अभिकरण इन नियमों के अधीन ग्रीन क्रेडिट जारी करने हेतु आवेदक द्वारा किए गए कार्यों के सत्यापन के संबंध में दिशानिर्देशों के अनुसार सत्यापन करवाएगा और प्रशासक को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा;

(3) अभिहित अभिकरण दिशानिर्देशों के अनुसार प्रशासक को वार्षिक विवरणियां प्रस्तुत करेगा।

14. ग्रीन क्रेडिट हेतु मांग उत्पन्न करना - (1) इन नियमों के अधीन ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम में भागीदारी स्वैच्छिक भागीदारी पर आधारित होगी।

(2) संचालन समिति देश में ग्रीन क्रेडिट की मांग उत्पन्न करने के उपायों की सिफारिश करेगी।

15. लेखापरीक्षक. - (1) प्रशासक, अभिहित अभिकरण, रजिस्ट्री, व्यापार मंच और ज्ञान एवं डेटा मंच के कार्यों की प्रत्येक तीसरे वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर एक वर्ष के भीतर संचालन समिति की अनुशंसा पर केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त स्वतंत्र लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षा करवाई जाएगी।

(2) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट लेखा परीक्षक अपना लेखा परीक्षा प्रतिवेदन प्रशासक को प्रस्तुत करेगा।

(3) प्रशासक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की प्राप्ति की तारीख से छह मास के भीतर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट केंद्रीय सरकार को प्रस्तुत करेगा।

[फा. सं.12/24/2023 – एचएसएम (पीटी2)]

नमिता प्रसाद, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th October, 2023

S.O. 4458 (E).—WHEREAS a Green Credit programme is being launched at national level to leverage a competitive market-based approach for green credit for incentivising environmental actions of various stakeholders;

AND WHEREAS the Government of India has introduced 'LiFE'-'Lifestyle for Environment', as a grass-root, mass movement, for protection and conservation of environment and for other environmental and climate gains, by enhancing environmental actions that propagate a healthy and sustainable way of living based on traditions and values of conservation and moderation, and for sustainable and environment-friendly development;

AND WHEREAS an innovative market-based mechanism to incentivise environment positive actions will help promote the LiFE movement, which aims at encouraging sustainable lifestyles by driving consumer and community towards behavioural changes that promote environment friendly actions;

AND WHEREAS the Green Credit programme is independent of the carbon credit under the Carbon Credit Trading Scheme, 2023 made under the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), an environmental activity generating green credit may have climate co-benefits, such as reduction or removal of carbon emissions and an activity generating green credit under Green Credit programme may also get carbon credit from the same activity under the said Scheme;

AND WHEREAS the draft Green Credit Programme Implementation Rules, 2023 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* notification number S.O. 2779(E), dated the 26th June 2023 inviting objections and suggestions from all persons;

AND WHEREAS all the objections and suggestions received have been duly considered by the Central Government;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by section 3, section 6 and section 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Green Credit Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Objectives of Green Credit programme.— (1) The green credit programme shall incentivise environmental positive actions through market-based mechanism and generate green credit, which shall be tradable and made available for trading on a domestic market platform.

(2) The green credit will arise from taking measures by a person of any environment activities referred to in sub-rule (2) of rule 4.

(3) The green credit programme shall encourage industries, companies and other entities to meet their existing obligations or other obligations under any law for the time being in force, and encourage other persons and entities, to undertake voluntary environmental measures referred to in rule 4 by generating or buying green credit:

Provided that the green credit generated or procured to fulfil any obligation in compliance of any law for the time being in force shall not be tradable.

3. Definitions.— (1) In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Administrator" means the Administrator referred to in rule 7;

(b) "designated agency" means an entity designated as such under rule 13;

(c) "Green Credit" means a singular unit of an incentive provided for a specified activity, delivering a positive impact on the environment;

(d) "Registry" means the Green Credit Registry established under rule 10.

(2) Words and expressions used in these rules and not defined herein but defined in the Environment (Protection) Act, 1986, shall have the same meaning as assigned to them in the Act.

4. Green Credit programme.— (1) Any person or entity may take any measure specified under sub-rule (2) for the purposes of protection, preservation, or conservation of the environment.

(2) The measures referred to in sub-rule (1) may include the following activities, namely:—

(i) tree plantation—to promote activities for increasing the green cover across the country;

(ii) water management—to promote water conservation, water harvesting and water use efficiency or water savings, including treatment and reuse of wastewater;

(iii) sustainable agriculture—to promote natural and regenerative agricultural practices and land restoration to improve productivity, soil health and nutritional value of food produced;

(iv) waste management—to promote circularity, sustainable and improved practices for waste management, including collection, segregation, and environmentally sound management;

(v) air pollution reduction—to promote measures for reducing air pollution and other pollution abatement activities;

(vi) mangrove conservation and restoration—to promote measures for conservation and restoration of mangroves;

(vi) ecomark label development—to encourage manufacturers to obtain ecomark label for their goods and services;

(vii) sustainable building and infrastructure—to encourage the construction of sustainable buildings and other infrastructure using environment friendly technologies and materials.

(3) A person or entity desirous of obtaining green credit shall register the activity with the Administrator for any activity referred to in sub-rule (2) undertaken by him for grant of green credit.

(4) An application for registration under sub-rule (3) shall be made to the Administrator electronically through a website established by the Central Government for that purpose.

(5) On receipt of the application under sub-rule (4), the Administrator shall cause the activity to be verified by a designated agency.

(6) The designated agency shall, after making such verification and inquiry as it may deem necessary, in accordance with the guideline made in this behalf, submit a report to the Administrator verifying the activities undertaken by the applicant.

(7) On receipt of the report under sub-rule (6) verifying the activities undertaken by the applicant, the Administrator shall grant the applicant a certificate of green credit.

5. Methodology of generating green credit.—(1) The methodology for calculating the green credit in respect of any activity undertaken shall be such as may be notified by the Central Government on the recommendation of the Administrator.

(2) The calculation of green credit in respect of any activity undertaken shall be based on equivalence of resource requirement, parity of scale, scope, size and other relevant parameters required to achieve the desired environmental outcome.

6. Procedure for generation of green credit.— (1) The methodology for evaluation and verification of the activities undertaken for the purpose of calculation of green credit shall be such as may be determined by the Administrator.

(2) The manner of registration of the activities and the details required for such registration shall be determined by the Administrator.

(3) The Administrator shall develop the website for registration of activities, evaluation and verification of activities undertaken and award of green credit in respect of such verified activities, electronically.

7. Administrator.— (1) The Indian Council of Forestry Research and Education, a Society registered under the Societies Registration Act, 1860 (21 of 1860) vide Registration No.596/1990-91, dated the 12th March, 1991 and an autonomous body as declared by the then Ministry of Environment and Forests, Government of India vide Resolution No.1-8/89-RT, dated the 22nd June, 1990, shall be the Administrator under these rules.

(2) The Administrator shall be responsible for the effective implementation of the Green Credit programme, including its management and operation under these rules.

(3) The responsibilities of the Administrator shall include the following, namely:—

(a) develop guidelines, processes and procedures for the implementation of the green credit programme under these rules;

(b) develop methodologies, registration process, guidelines and associated measurement, reporting and verification mechanism;

(c) establish methodologies and processes for issuance of green credit (including issuance of digital green credit), and equivalence of green credit generated from each identified activity;

(d) develop guidelines for the establishment and operation of the Green Credit Registry and trading platform; for self-certification or third-party certification for the registration of an activity for issuance of green credits and its inspection and verification by designated agency, for empanelment of auditors and audit by such auditors;

(e) establish or designate the Green Credit Registry, and trading platform service provider in accordance with the approved guidelines;

(f) develop guidelines for the green credit programme portal, the knowledge and data platform, and for the fees from the registered entities;

(g) develop guidelines for filing of annual returns and progress reports by designated agency, Registry, trading platform and knowledge and data platform;

(h) develop guidelines for the market stability mechanism for trading of green credit.

(i) regulate matters relating to trading of green credit certificates and to safeguard interest of sellers and buyers; and take preventive and corrective actions to prevent fraud or mistrust.

(4) The Administrator shall seek approval of the Central Government for guidelines and methodologies under sub-rule (3).

8. Steering Committee.— (1) A Steering Committee to be constituted by the Central Government shall be responsible for the monitoring of the implementation of the Green Credit programme under these rules.

(2) The Steering Committee shall comprise of representatives from the Ministries or Departments, experts from the field of environment, industry associations and other relevant stakeholders as the Central Government may consider appropriate.

(3) The Steering Committee shall, from time to time, review the Green Credit programme under these rules and make recommendations to the Central Government in respect of following, namely:—

(a) activities and sectors to be included in the Green Credit programme; and

(b) any matter referred to it by the Central Government.

9. Technical Committee.— (1) The Central Government, based on the recommendations of the Administrator, may constitute Technical Committees for each activity which shall assist the Administrator in implementation of the Green Credit programme under these rules.

(2) Each Technical Committee shall comprise of members from the Ministries and Departments, organisations and experts having the knowledge and experience in the field related to the activity;

(3) Technical Committee shall develop and make recommendations to the Administrator which will inter alia include—

(a) methodology for calculation of one unit of Green Credit, on the basis of equivalence of resource requirement, parity of scale, scope, size and other relevant parameters required to achieve the desired environmental outcome;

(b) mechanism for registration, verification, evaluation, measurement and reporting process in respect of each activity.

(4) The Technical Committee shall advise on any other technical matter referred to it by the Administrator.

10. Green Credit Registry.— (1) The Administrator or designated agency shall establish and maintain a Green Credit Registry for the registration and issuance of each Green Credit.

(2) The Registry shall be an electronic database, which, inter alia, shall contain common data elements relevant to the registration and issuance of green credit.

(3) The Registry shall discharge the following functions, namely:—

(a) registration of activities and issuance of green credit;

(b) ensure accurate accounting of the issuance of green credit;

(c) maintain secure database with all required and essential security protocols;

(d) any other function assigned to it by the Administrator.

11. Trading platform.— (1) The Administrator shall establish and maintain a trading platform with the approval of the Central Government.

(2) The trading platform shall perform functions regarding the trading of green credit, in accordance with the guidelines made by the Administrator with the approval of the Central Government.

12. Knowledge and data platform.— (1) The Administrator shall develop and maintain a knowledge and data platform, with approval of the Central Government, for providing transparency on various activities being undertaken and for reporting sectoral progress under these rules.

(2) The knowledge and data platform may collate key data points generated from the Registry and other information, such as sectoral achievements, best practices, information on capacity building, etc.

13. Designated agency.— (1) The Administrator shall designate such entities to act as designated agency in accordance with the guidelines approved by the Central Government.

(2) The designated agency shall conduct verification and submit reports to the Administrator in accordance with the guidelines as regard to the verification of the activities undertaken by an applicant for issuance of green credit under these rules.;

(3) The designated agency shall file annual returns to the Administrator in accordance with the guidelines.

14. Demand generation for green credit.— (1) The participation to the Green Credit programme under these rules shall be based on voluntary participation.

(2) The Steering Committee shall recommend measures to generate demand for green credit in the country.

15. Auditors.— (1) The activities of the Administrator, designated agency, Registry, trading platform and knowledge and data platform shall be audited within a period of one year at the end of every third financial year by independent auditors to be appointed by the Central Government on the recommendation of the Steering Committee.

(2) The auditor referred to in sub-rule (1) shall submit its audit report to the Administrator.

(3) The Administrator shall submit an action taken report on the audit report to the Central Government within a period of six months from the date of the receipt of the audit report.

[F. No.12/24/2023–HSM(pt2)]

NAMEETA PRASAD, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99

REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13102023-249377
CG-DL-E-13102023-249377

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4287] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 12, 2023/आश्विन 20, 1945
No. 4287] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 12, 2023/ASVINA 20, 1945

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 अक्तूबर, 2023

का.आ. 4458(अ).—विभिन्न पणधारकों के पर्यावरण अनुकूल कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिए ग्रीन क्रेडिट हेतु बाजार-आधारित दृष्टिकोण का लाभ उठाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम आरंभ किया जा रहा है;

और भारत सरकार ने पर्यावरण की सुरक्षा एवं संरक्षण और पर्यावरण अनुकूल कार्यों, जो संरक्षण एवं संयम की परंपराओं एवं मूल्यों पर आधारित जीवन जीने के स्वस्थ एवं सतत तरीके का प्रचार करते हों, को बढ़ाकर अन्य पर्यावरणीय एवं जलवायु लाभों के लिए और सतत एव पर्यावरण हितैषी विकास के लिए भू स्तर पर, जन आंदोलन के रूप में 'लाइफ' - 'पर्यावरण हेतु जीवन शैली' का प्रारम्भ है;

और पर्यावरण के प्रति सकारात्मक कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिए बाजार-आधारित अभिनव तंत्र "लाइफ" आंदोलन को बढ़ावा देने में सहायता करेगा, जिसका उद्देश्य उपभोक्ताओं और समाज को पर्यावरण अनुकूल कार्यों को बढ़ावा देने वाले व्यवहारिक परिवर्तनों की ओर प्रेरित करके सतत जीवन शैली को प्रोत्साहित करना है;

और ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) के अधीन बनाई गई कार्बन क्रेडिट व्यापार स्कीम, 2023 से पृथक है, ग्रीन क्रेडिट प्रदान करने वाले पर्यावरणीय कार्यों से जलवायु संबंधी लाभ भी हो सकते हैं, जैसे कार्बन उत्सर्जन को कम करना या समाप्त करना और ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम के अधीन ग्रीन क्रेडिट प्रदान करने वाला कार्य, उक्त स्कीम के अधीन उसी कार्य के लिए कार्बन क्रेडिट भी प्राप्त किया जा सकेगा;

और ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम कार्यान्वयन नियम, 2023 का प्रारूप भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में अधिसूचना संख्या का.आ. 2779 (अ), तारीख 26 जून, 2023 द्वारा प्रकाशित किया गया था जिसमें सभी व्यक्तियों से आपत्तियाँ और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और केंद्रीय सरकार द्वारा प्राप्त सभी आपत्तियों और सुझावों पर सम्यक रूप से विचार किया गया है;

अतः अब, केंद्रीय सरकार पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29), धारा 3, धारा 6 और धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्: -

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** — (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम ग्रीन क्रेडिट नियम, 2023 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम के उद्देश्य. - (1) ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम बाजार-आधारित तंत्र के माध्यम से पर्यावरण हेतु सकारात्मक कार्यों को प्रोत्साहित करेगा और ग्रीन क्रेडिट प्रदान करेगा, जिससे व्यापार कर पाएंगे और ये घरेलू बाजार मंच पर व्यापार हेतु उपलब्ध कराए जाएंगे।

(2) ग्रीन क्रेडिट नियम 4 के उप-नियम (2) में निर्दिष्ट किसी भी पर्यावरणीय कार्य के लिए किसी व्यक्ति द्वारा किए गए उपाय से प्राप्त होगा।

(3) ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम उद्योगों, कंपनियों और अन्य संस्थाओं को वर्तमान में प्रवृत्त किसी भी विधि के अंतर्गत विद्यमान दायित्वों या अन्य दायित्वों को पूरा करने के साथ-साथ नियम 4 में निर्दिष्ट स्वैच्छिक पर्यावरणीय उपाय करने हेतु अन्य व्यक्तियों, और इकाइयों को सुविधा प्रदान करने के लिए ग्रीन क्रेडिट प्रदान कर या खरीदकर प्रोत्साहित करेगा;

परन्तु कि उस समय प्रवृत्त विधि की अनुपालना में पूरे किए गए दायित्व से सृजित या प्राप्त ग्रीन क्रेडिट व्यापार योग्य नहीं होगा।

3. परिभाषाएँ - (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(क) "प्रशासक" से नियम 7 में निर्दिष्ट प्रशासक अभिप्रेत है;

(ख) "अभिहित अभिकरण" से नियम 13 के अधीन ऐसी अभिहित कोई इकाई अभिप्रेत है;

(ग) "ग्रीन क्रेडिट" से किसी विशिष्ट कार्य, जिसका पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता हो, हेतु प्रदान किए गए प्रोत्साहन की एकल इकाई अभिप्रेत है;

(घ) "रजिस्ट्री" से तात्पर्य नियम 10 के अधीन स्थापित ग्रीन क्रेडिट रजिस्ट्री अभिप्रेत है।

(2) उन शब्दों और पदों के जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किंतु पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में है।

4. ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम - (1) कोई व्यक्ति या इकाई पर्यावरण की सुरक्षा, परिरक्षण या संरक्षण के प्रयोजनार्थ उप-नियम (2) में निर्दिष्ट कोई भी उपाय कर सकेगा।

(2) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट उपायों में निम्नलिखित कार्य सम्मिलित हैं, अर्थात्:-

(i) वृक्षारोपण – सम्पूर्ण देश में हरित आवरण बढ़ाने के लिए कार्यों को प्रोत्साहन हेतु;

(ii) जल प्रबंधन - जल संरक्षण, जल संचयन और जल के कुशल उपयोग या जल बचत को प्रोत्साहन हेतु, जिसमें अपशिष्ट जल का उपचार और पुनः उपयोग सम्मिलित है;

(iii) सतत कृषि - उत्पादकता, मृदा स्वास्थ्य और उत्पादित खाद्य के पोषण मूल्य में सुधार लाने हेतु प्राकृतिक एवं पुनर्योजी कृषि प्रथाओं और भूमि पुनरूद्धार को प्रोत्साहन हेतु;

(iv) अपशिष्ट प्रबंधन - संग्रहण, पृथक्करण और पर्यावरण की दृष्टि से सुदृढ़ प्रबंधन सहित अपशिष्ट प्रबंधन हेतु चक्रीयता, सततता और परिष्कृत प्रथाओं को प्रोत्साहन हेतु;

(v) वायु प्रदूषण में कमी लाना - वायु प्रदूषण में कमी लाने वाले उपायों और अन्य प्रदूषण उपशमन कार्यकलापों के प्रोत्साहन हेतु;

(vi) मैंग्रोव संरक्षण और पुनरूद्धार - मैंग्रोव के संरक्षण और पुनरूद्धार के उपायों को प्रोत्साहन हेतु;

(vi) इकोमार्क लेबल विकसित करना - विनिर्माताओं को अपने माल और सेवाओं हेतु इकोमार्क लेबल प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना;

(vii) सतत भवन और बुनियादी ढांचा - पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकियों और सामग्रियों का उपयोग करके सतत भवनों एवं अन्य आधारभूत ढांचे के निर्माण को प्रोत्साहित करना।

(3) ग्रीन क्रेडिट प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति या संस्था को उप-नियम (2) में निर्दिष्ट किसी भी कार्य हेतु ग्रीन क्रेडिट लेने के लिए उनके द्वारा किए गए कार्य को प्रशासक के पास रजिस्टर करना होगा।

(4) उप-नियम (3) के अधीन रजिस्ट्रीकरण हेतु आवेदन केंद्रीय सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ स्थापित वेबसाइट के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रशासक को किया जाएगा।

(5) उप-नियम (4) के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर, प्रशासक कार्य को किसी अभिहित अभिकरण द्वारा सत्यापित कराएगा।

(6) अभिहित अभिकरण, इस संबंध में बनाए गए दिशानिर्देशों के अनुसार, सत्यापन एवं पूछताछ, यथावश्यक, के पश्चात, आवेदक द्वारा किए गए कार्यों की पुष्टि करते हुए प्रशासक को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(7) आवेदक द्वारा किए गए कार्यों की पुष्टि करते हुए उप-नियम (6) के अधीन रिपोर्ट प्राप्त होने पर, प्रशासक आवेदक को ग्रीन क्रेडिट का प्रमाण पत्र प्रदान करेगा।

5. ग्रीन क्रेडिट उत्पन्न करने की पद्धति - (1) किसी भी कार्य के संदर्भ में ग्रीन क्रेडिट की गणना करने की पद्धति इस प्रकार होगी, जो प्रशासक की सिफारिशों पर केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए ।

(2) किए गए किसी भी कार्य के संदर्भ में ग्रीन क्रेडिट की गणना वांछित पर्यावरणीय परिणाम प्राप्त करने हेतु आवश्यक संसाधन, समान स्केल, क्षेत्र, आकार एवं अन्य प्रासंगिक मापदंडों की समकक्षता पर आधारित होगी।

(3) नियम (4) के अधीन निर्दिष्ट कार्यों हेतु ग्रीन क्रेडिट उत्पन्न करने और जारी करने की पद्धतियाँ केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाएंगी।

6. ग्रीन क्रेडिट उत्पन्न करने की प्रक्रिया - (1) ग्रीन क्रेडिट की गणना के प्रयोजनार्थ किए गए कार्यों के मूल्यांकन और सत्यापन की पद्धति इस प्रकार होगी, जो प्रशासक द्वारा निर्धारित की जाए।

(2) कार्यों के रजिस्ट्रीकरण का तरीका और इस प्रकार के रजिस्ट्रीकरण हेतु अपेक्षित विवरण प्रशासक द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

(3) प्रशासक कार्यों के रजिस्ट्रीकरण, किए गए कार्यों के मूल्यांकन एवं सत्यापन और इस प्रकार सत्यापित कार्यों के के संबंध में इलेक्ट्रॉनिक रूप से ग्रीन क्रेडिट प्रदान करने हेतु वेबसाइट विकसित करेगा।

7. प्रशासक - (1) भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद, सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 का सं. 21 के अधीन रजिस्ट्रीकरण संख्या 596/1990-91 के अधीन रजिस्ट्रीकरण सोसायटी तारीख 12 मार्च, 1991 द्वारा स्थापित और तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा फा. सं.1-8/89-आरटी, तारीख 22 जून, 1990 के माध्यम से यथाघोषित एक स्वायत्त निकाय, इन नियमों के अधीन प्रशासक होगा।

(2) प्रशासक इन नियमों के अधीन इसके प्रबंधन और संचालन सहित ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी होगा।

(3) प्रशासक के उत्तरदायित्वों में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे, अर्थात्: -

(क) इन नियमों के अधीन ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देश, प्रक्रियाएं और कार्य प्रणाली विकसित करना;

(ख) पद्धतियां, रजिस्ट्रीकरण प्रक्रिया, दिशानिर्देश और संबंधित माप, रिपोर्टिंग और सत्यापन हेतु तंत्र विकसित करना;

(ग) ग्रीन क्रेडिट (डिजिटल ग्रीन क्रेडिट जारी करने सहित) और प्रत्येक चिह्नित कार्य से उत्पन्न ग्रीन क्रेडिट का समतुल्य जारी करने हेतु कार्यप्रणाली और प्रक्रियाएं स्थापित करना;

(घ) ग्रीन क्रेडिट रजिस्ट्री और व्यापार मंच की स्थापना और संचालन हेतु; ग्रीन क्रेडिट जारी करने हेतु किसी कार्य के रजिस्ट्रीकरण के लिए स्व-प्रमाणन या तृतीय पक्ष प्रमाणन हेतु; अभिहित अभिकरण द्वारा इसके निरीक्षण और सत्यापन हेतु और लेखा-परीक्षकों का पैनल बनाने एवं ऐसे लेखा-परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षा करने हेतु दिशानिर्देश विकसित करना;

(ङ) अनुमोदित दिशानिर्देशों के अनुसार ग्रीन क्रेडिट रजिस्ट्री व्यापार मंच सेवा प्रदाता की स्थापना या नामित करना;

(च) ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम पोर्टल, ज्ञान एवं डेटा मंच और रजिस्ट्रीकरण संस्थाओं से शुल्क के लिए दिशानिर्देश विकसित करना;

(छ) नामित अभिकरण, रजिस्ट्री, व्यापार मंच और ज्ञान एवं डेटा मंच द्वारा वार्षिक विवरणियां एवं प्रगति प्रतिवेदन दर्ज करने के लिए दिशानिर्देश विकसित करना;

(ज) ग्रीन क्रेडिट के व्यापार हेतु बाजार स्थिरता तंत्र के लिए दिशानिर्देश विकसित करना।

(झ) ग्रीन क्रेडिट प्रमाणपत्रों के व्यापार से संबंधित मामलों को विनियमित करना और विक्रेताओं और क्रेताओं दोनों के हितों की रक्षा करना और धोखाधड़ी या अविश्वास को रोकने के लिए निवारक एवं सुधारात्मक कार्रवाई करना।

(4) प्रशासक उपरोक्त उपनियम (3) के अधीन दिशानिर्देशों एवं पद्धतियों हेतु केंद्रीय सरकार का अनुमोदन प्राप्त करेगा।

8. संचालन समिति - (1) केंद्रीय सरकार द्वारा गठित की जाने वाली संचालन समिति इन नियमों के अधीन ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम के कार्यान्वयन की निगरानी हेतु उत्तरदायी होगी।

(2) संचालन समिति में मंत्रालयों या विभागों के प्रतिनिधि, पर्यावरण क्षेत्र के विशेषज्ञ, उद्योग संघ और अन्य प्रासंगिक पणधारक सम्मिलित होंगे जिन्हें केंद्रीय सरकार उचित समझे।

(3) संचालन समिति, समय-समय पर, इन नियमों के अधीन ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम की समीक्षा करेगी और निम्नलिखित के संबंध में केंद्रीय सरकार को सिफारिशें करेगी, अर्थात्:-

(क) ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम में सम्मिलित किए जाने वाले कार्य और क्षेत्र के संबंध में; और

(ख) केंद्रीय सरकार द्वारा इसको संदर्भित किसी भी मामले के संदर्भ में।

9. तकनीकी समिति — (1) केंद्रीय सरकार, प्रशासक की सिफ़ारिशों के आधार पर प्रत्येक कार्य हेतु तकनीकी समितियों का गठन कर सकेंगी, जो इन नियमों के अधीन ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम के कार्यान्वयन में प्रशासक की सहायता करेगी।

(2) प्रत्येक तकनीकी समिति के सदस्यों में मंत्रालयों एवं विभागों, संगठनों और उस कार्य से संबंधित क्षेत्र में ज्ञान और अनुभव रखने वाले विशेषज्ञ सम्मिलित होंगे;

(3) तकनीकी समिति सिफारिशें विकसित करेगी और प्रशासक को प्रेषित करेगी जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित सम्मिलित भी होगा –

(क) वांछित पर्यावरणीय परिणाम प्राप्त करने हेतु आवश्यक संसाधन, समान स्केल, क्षेत्र, आकार एवं अन्य प्रासंगिक मापदंडों की समकक्षता के आधार पर ग्रीन क्रेडिट की एक इकाई की गणना के लिए पद्धति;

(ख) प्रत्येक कार्य के संबंध में रजिस्ट्रीकरण, सत्यापन, मूल्यांकन, माप और रिपोर्टिंग प्रक्रिया के लिए तंत्र।

(4) प्रशासक द्वारा तकनीकी समिति को निर्दिष्ट किसी भी अन्य तकनीकी मामले पर यह परामर्श देगी।

10. ग्रीन क्रेडिट रजिस्ट्री - (1) प्रशासक या नामित अभिकरण प्रत्येक ग्रीन क्रेडिट का रजिस्ट्रीकरण करने एवं जारी करने हेतु ग्रीन क्रेडिट रजिस्ट्री की स्थापना एवं रखरखाव करेगी।

(2) रजिस्ट्री इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस होगी, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, रजिस्ट्रीकरण एवं ग्रीन क्रेडिट जारी करने से संबंधित सामान्य डेटा तत्व सम्मिलित होंगे।

(3) रजिस्ट्री निम्नलिखित कार्यों का निर्वहन करेगी, अर्थात्: -

(क) कार्यों का रजिस्ट्रीकरण और ग्रीन क्रेडिट जारी करना;

(ख) ग्रीन क्रेडिट जारी करने का सटीक लेखा-जोखा सुनिश्चित करना;

(ग) सभी आवश्यक एवं अनिवार्य सुरक्षा प्रोटोकॉल के साथ सुरक्षित डेटाबेस बनाए रखना;

(घ) प्रशासक द्वारा इसे सौंपा गया कोई अन्य कार्य।

11. ट्रेडिंग प्लेटफार्म - (1) प्रशासक केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से (व्यापार मंच) ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की स्थापना करेगा एवं उसका रखरखाव करेगा।

(2) ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से प्रशासक द्वारा बनाए गए दिशानिर्देशों के अनुसार, ग्रीन क्रेडिट के व्यापार संबंधी कार्य करेगा।

12. ज्ञान एवं डेटा मंच - (1) प्रशासक किए जा रहे विभिन्न कार्यों के संबंध में पारदर्शिता प्रदान करने और इन नियमों के अधीन क्षेत्रवार प्रगति की रिपोर्ट करने हेतु, केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से, ज्ञान एवं डेटा मंच विकसित करेगा एवं उसका रखरखाव करेगा।

(2) ज्ञान एवं डेटा मंच रजिस्ट्री से उत्पन्न प्रमुख डेटा बिंदुओं और अन्य जानकारी, जैसे क्षेत्रवार उपलब्धियां, सर्वोत्तम प्रथाएं, क्षमता निर्माण संबंधी जानकारी आदि को संगृहीत कर सकेगा।

13. अभिहित अभिकरण - (1) प्रशासक ऐसी संस्थाओं को केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित दिशानिर्देशों के अनुसार अभिहित अभिकरण के रूप में कार्य करने के लिए संस्थाओं को नामित करेगा।

(2) अभिहित अभिकरण इन नियमों के अधीन ग्रीन क्रेडिट जारी करने हेतु आवेदक द्वारा किए गए कार्यों के सत्यापन के संबंध में दिशानिर्देशों के अनुसार सत्यापन करवाएगा और प्रशासक को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा;

(3) अभिहित अभिकरण दिशानिर्देशों के अनुसार प्रशासक को वार्षिक विवरणियां प्रस्तुत करेगा।

14. ग्रीन क्रेडिट हेतु मांग उत्पन्न करना - (1) इन नियमों के अधीन ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम में भागीदारी स्वैच्छिक भागीदारी पर आधारित होगी।

(2) संचालन समिति देश में ग्रीन क्रेडिट की मांग उत्पन्न करने के उपायों की सिफारिश करेगी।

15. लेखापरीक्षक. - (1) प्रशासक, अभिहित अभिकरण, रजिस्ट्री, व्यापार मंच और ज्ञान एवं डेटा मंच के कार्यों की प्रत्येक तीसरे वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर एक वर्ष के भीतर संचालन समिति की अनुशंसा पर केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त स्वतंत्र लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षा करवाई जाएगी।

(2) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट लेखा परीक्षक अपना लेखा परीक्षा प्रतिवेदन प्रशासक को प्रस्तुत करेगा।

(3) प्रशासक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की प्राप्ति की तारीख से छह मास के भीतर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट केंद्रीय सरकार को प्रस्तुत करेगा।

[फा. सं.12/24/2023 – एचएसएम (पीटी2)]

नमिता प्रसाद, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th October, 2023

S.O. 4458 (E).—WHEREAS a Green Credit programme is being launched at national level to leverage a competitive market-based approach for green credit for incentivising environmental actions of various stakeholders;

AND WHEREAS the Government of India has introduced 'LiFE'-'Lifestyle for Environment', as a grass-root, mass movement, for protection and conservation of environment and for other environmental and climate gains, by enhancing environmental actions that propagate a healthy and sustainable way of living based on traditions and values of conservation and moderation, and for sustainable and environment-friendly development;

AND WHEREAS an innovative market-based mechanism to incentivise environment positive actions will help promote the LiFE movement, which aims at encouraging sustainable lifestyles by driving consumer and community towards behavioural changes that promote environment friendly actions;

AND WHEREAS the Green Credit programme is independent of the carbon credit under the Carbon Credit Trading Scheme, 2023 made under the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), an environmental activity generating green credit may have climate co-benefits, such as reduction or removal of carbon emissions and an activity generating green credit under Green Credit programme may also get carbon credit from the same activity under the said Scheme;

AND WHEREAS the draft Green Credit Programme Implementation Rules, 2023 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* notification number S.O. 2779(E), dated the 26th June 2023 inviting objections and suggestions from all persons;

AND WHEREAS all the objections and suggestions received have been duly considered by the Central Government;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by section 3, section 6 and section 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Green Credit Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Objectives of Green Credit programme.— (1) The green credit programme shall incentivise environmental positive actions through market-based mechanism and generate green credit, which shall be tradable and made available for trading on a domestic market platform.

(2) The green credit will arise from taking measures by a person of any environment activities referred to in sub-rule (2) of rule 4.

(3) The green credit programme shall encourage industries, companies and other entities to meet their existing obligations or other obligations under any law for the time being in force, and encourage other persons and entities, to undertake voluntary environmental measures referred to in rule 4 by generating or buying green credit:

Provided that the green credit generated or procured to fulfil any obligation in compliance of any law for the time being in force shall not be tradable.

3. Definitions.— (1) In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Administrator" means the Administrator referred to in rule 7;

(b) "designated agency" means an entity designated as such under rule 13;

(c) "Green Credit" means a singular unit of an incentive provided for a specified activity, delivering a positive impact on the environment;

(d) "Registry" means the Green Credit Registry established under rule 10.

(2) Words and expressions used in these rules and not defined herein but defined in the Environment (Protection) Act, 1986, shall have the same meaning as assigned to them in the Act.

4. Green Credit programme.— (1) Any person or entity may take any measure specified under sub-rule (2) for the purposes of protection, preservation, or conservation of the environment.

(2) The measures referred to in sub-rule (1) may include the following activities, namely:—

(i) tree plantation—to promote activities for increasing the green cover across the country;

(ii) water management—to promote water conservation, water harvesting and water use efficiency or water savings, including treatment and reuse of wastewater;

(iii) sustainable agriculture—to promote natural and regenerative agricultural practices and land restoration to improve productivity, soil health and nutritional value of food produced;

(iv) waste management—to promote circularity, sustainable and improved practices for waste management, including collection, segregation, and environmentally sound management;

(v) air pollution reduction—to promote measures for reducing air pollution and other pollution abatement activities;

(vi) mangrove conservation and restoration—to promote measures for conservation and restoration of mangroves;

(vi) ecomark label development—to encourage manufacturers to obtain ecomark label for their goods and services;

(vii) sustainable building and infrastructure—to encourage the construction of sustainable buildings and other infrastructure using environment friendly technologies and materials.

(3) A person or entity desirous of obtaining green credit shall register the activity with the Administrator for any activity referred to in sub-rule (2) undertaken by him for grant of green credit.

(4) An application for registration under sub-rule (3) shall be made to the Administrator electronically through a website established by the Central Government for that purpose.

(5) On receipt of the application under sub-rule (4), the Administrator shall cause the activity to be verified by a designated agency.

(6) The designated agency shall, after making such verification and inquiry as it may deem necessary, in accordance with the guideline made in this behalf, submit a report to the Administrator verifying the activities undertaken by the applicant.

(7) On receipt of the report under sub-rule (6) verifying the activities undertaken by the applicant, the Administrator shall grant the applicant a certificate of green credit.

5. Methodology of generating green credit.—(1) The methodology for calculating the green credit in respect of any activity undertaken shall be such as may be notified by the Central Government on the recommendation of the Administrator.

(2) The calculation of green credit in respect of any activity undertaken shall be based on equivalence of resource requirement, parity of scale, scope, size and other relevant parameters required to achieve the desired environmental outcome.

6. Procedure for generation of green credit.— (1) The methodology for evaluation and verification of the activities undertaken for the purpose of calculation of green credit shall be such as may be determined by the Administrator.

(2) The manner of registration of the activities and the details required for such registration shall be determined by the Administrator.

(3) The Administrator shall develop the website for registration of activities, evaluation and verification of activities undertaken and award of green credit in respect of such verified activities, electronically.

7. Administrator.— (1) The Indian Council of Forestry Research and Education, a Society registered under the Societies Registration Act, 1860 (21 of 1860) vide Registration No.596/1990-91, dated the 12th March, 1991 and an autonomous body as declared by the then Ministry of Environment and Forests, Government of India vide Resolution No.1-8/89-RT, dated the 22nd June, 1990, shall be the Administrator under these rules.

(2) The Administrator shall be responsible for the effective implementation of the Green Credit programme, including its management and operation under these rules.

(3) The responsibilities of the Administrator shall include the following, namely:—

(a) develop guidelines, processes and procedures for the implementation of the green credit programme under these rules;

(b) develop methodologies, registration process, guidelines and associated measurement, reporting and verification mechanism;

(c) establish methodologies and processes for issuance of green credit (including issuance of digital green credit), and equivalence of green credit generated from each identified activity;

(d) develop guidelines for the establishment and operation of the Green Credit Registry and trading platform; for self-certification or third-party certification for the registration of an activity for issuance of green credits and its inspection and verification by designated agency, for empanelment of auditors and audit by such auditors;

(e) establish or designate the Green Credit Registry, and trading platform service provider in accordance with the approved guidelines;

(f) develop guidelines for the green credit programme portal, the knowledge and data platform, and for the fees from the registered entities;

(g) develop guidelines for filing of annual returns and progress reports by designated agency, Registry, trading platform and knowledge and data platform;

(h) develop guidelines for the market stability mechanism for trading of green credit.

(i) regulate matters relating to trading of green credit certificates and to safeguard interest of sellers and buyers; and take preventive and corrective actions to prevent fraud or mistrust.

(4) The Administrator shall seek approval of the Central Government for guidelines and methodologies under sub-rule (3).

8. Steering Committee.— (1) A Steering Committee to be constituted by the Central Government shall be responsible for the monitoring of the implementation of the Green Credit programme under these rules.

(2) The Steering Committee shall comprise of representatives from the Ministries or Departments, experts from the field of environment, industry associations and other relevant stakeholders as the Central Government may consider appropriate.

(3) The Steering Committee shall, from time to time, review the Green Credit programme under these rules and make recommendations to the Central Government in respect of following, namely:—

(a) activities and sectors to be included in the Green Credit programme; and

(b) any matter referred to it by the Central Government.

9. Technical Committee.— (1) The Central Government, based on the recommendations of the Administrator, may constitute Technical Committees for each activity which shall assist the Administrator in implementation of the Green Credit programme under these rules.

(2) Each Technical Committee shall comprise of members from the Ministries and Departments, organisations and experts having the knowledge and experience in the field related to the activity;

(3) Technical Committee shall develop and make recommendations to the Administrator which will inter alia include—

(a) methodology for calculation of one unit of Green Credit, on the basis of equivalence of resource requirement, parity of scale, scope, size and other relevant parameters required to achieve the desired environmental outcome;

(b) mechanism for registration, verification, evaluation, measurement and reporting process in respect of each activity.

(4) The Technical Committee shall advise on any other technical matter referred to it by the Administrator.

10. Green Credit Registry.— (1) The Administrator or designated agency shall establish and maintain a Green Credit Registry for the registration and issuance of each Green Credit.

(2) The Registry shall be an electronic database, which, inter alia, shall contain common data elements relevant to the registration and issuance of green credit.

(3) The Registry shall discharge the following functions, namely:—

(a) registration of activities and issuance of green credit;

(b) ensure accurate accounting of the issuance of green credit;

(c) maintain secure database with all required and essential security protocols;

(d) any other function assigned to it by the Administrator.

11. Trading platform.— (1) The Administrator shall establish and maintain a trading platform with the approval of the Central Government.

(2) The trading platform shall perform functions regarding the trading of green credit, in accordance with the guidelines made by the Administrator with the approval of the Central Government.

12. Knowledge and data platform.— (1) The Administrator shall develop and maintain a knowledge and data platform, with approval of the Central Government, for providing transparency on various activities being undertaken and for reporting sectoral progress under these rules.

(2) The knowledge and data platform may collate key data points generated from the Registry and other information, such as sectoral achievements, best practices, information on capacity building, etc.

13. Designated agency.— (1) The Administrator shall designate such entities to act as designated agency in accordance with the guidelines approved by the Central Government.

(2) The designated agency shall conduct verification and submit reports to the Administrator in accordance with the guidelines as regard to the verification of the activities undertaken by an applicant for issuance of green credit under these rules.;

(3) The designated agency shall file annual returns to the Administrator in accordance with the guidelines.

14. Demand generation for green credit.— (1) The participation to the Green Credit programme under these rules shall be based on voluntary participation.

(2) The Steering Committee shall recommend measures to generate demand for green credit in the country.

15. Auditors.— (1) The activities of the Administrator, designated agency, Registry, trading platform and knowledge and data platform shall be audited within a period of one year at the end of every third financial year by independent auditors to be appointed by the Central Government on the recommendation of the Steering Committee.

(2) The auditor referred to in sub-rule (1) shall submit its audit report to the Administrator.

(3) The Administrator shall submit an action taken report on the audit report to the Central Government within a period of six months from the date of the receipt of the audit report.

[F. No.12/24/2023–HSM(pt2)]

NAMEETA PRASAD, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

1883
22/08/2024

File No.: P- L-13007/6/2024-P- L
Government of India
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
Policy and Law Section
*****

Office of the P.C.C.F
Inward No. 5412
Book No. 05/24
Dt. 22/8/24

Level III, Jal Wing,
Indira Paryavaran Bhawan,
Jor Bagh, Aliganj,
New Delhi-110003

Dated:07th August, 2024

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Circulation of Information related to the new criminal laws i.e. Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS), 2023; Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita (BNSS), 2023; and Bharatiya Sakshya Adhiniyam (BSA), 2023- reg.

The undersigned is directed to enclose a copy of the D.O. letter No. 01/03/2023-Judl.Cell-I dated 17th July, 2024, received from the office of the Home Secretary, North Block, regarding the aforementioned subject.

2. Pursuant to Section 8 of the General Clauses Act, 1897, the Central Government has issued a notification dated 16th July, 2024, stipulating that references to the Indian Penal Code (IPC), the Code of Criminal Procedure (CrPC), the Indian Evidence Act, or any provisions thereof in any Act of Parliament or State Legislatures, including Ordinances, Presidential Orders, Rules, Regulations, Orders, or Notifications issued thereunder, shall be read as references to BNS, BNSS, or BSA, as applicable. The corresponding provisions of such laws shall be construed accordingly. A copy of the Gazette of India notification, S.O. 2790(E) dated 16th July, 2024, relating to these three criminal laws, is attached herewith for reference.

3. This issues with the approval of the competent authority.

Encl: as above.

(V.P. Rajvedi)
Under Secretary to the Govt. of India
I.C. No. 3126

To

All concerned Divisional Heads, MoEF&CC (to be forwarded to all organizations under their control)

Copy for Information to:

i. PPS to Secretary, EF&CC; (ii) PPS to DGF&SS; (iii) PPS to AS (TK); (iv) PPS to AS (NPG); (v) PPS to EA; and (vi) PS to Dir (P&L-NGT), MoEF&CC.

आज़ादी का अमृत महोत्सव

सत्यमेव जयते

Office of Secretary (EF&CC)
e-office No. 1230743
Date 19/07/24

G20 भारत 2023 INDIA वसुधैव कुटुम्बकम् ONE EARTH • ONE FAMILY • ONE FUTURE

अजय भल्ला, भा.प्र.से.
AJAY BHALLA, IAS

गृह सचिव
Home Secretary
भारत सरकार
Government of India
नॉर्थ ब्लॉक/North Block
नई दिल्ली/New Delhi

NEW CRIMINAL LAWS

O/o A.S. (TK)
Dy. No. 1230743
Date 22.7.24

D.O. No. 01/03/2023-Judl.Cell-I

17th July, 2024

Dear Secretary,

As you are aware, the three Criminal Laws viz. the Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS), 2023, the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita (BNSS), 2023 and the Bharatiya Sakshya Adhiniyam (BSA), 2023 to replace the Indian Penal Code (IPC), 1860, the Code of Criminal Procedure (CrPC), 1973 and the Indian Evidence Act (IEA), 1872 respectively, were notified on 25.12.2023 and have come into effect on 1st July, 2024.

2. Various Acts made by the Parliament or the State Legislatures, the Ordinances, President Orders; Rules, Regulations, Orders or Notifications issued under any Act, Ordinance etc., have reference of IPC, CrPC or IEA or provisions thereof. In pursuance of Section 8 of the General Clauses Act, 1897, the Central Government has issued a Notification on 16.07.2024 that where reference of IPC or CrPC or IEA or any provision thereof, in any Act made by the Parliament or the State Legislatures, the Ordinances, President Orders, Rules, Regulations, Orders or Notifications issued under the Act, Ordinances etc., such reference be read as reference of BNS, BNSS or BSA and the corresponding provisions of such laws shall be construed accordingly. A copy of the said Notification dated 16.07.2024 is enclosed for your information.

With regards,

O/o Joint Secretary (SKB)
Dy. No. 1230743
Date 22.7.2024

Yours sincerely,

Encl. as above

(Ajay Bhalla)

The Secretaries of Ministry/Deptt. of Government of India.
(as per standard list)

रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16072024-255467
CG-DL-E-16072024-255467

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2654] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 16, 2024/आषाढ 25, 1946
No. 2654] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 16, 2024/ASHADHA 25, 1946

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जुलाई, 2024

का.आ. 2790(अ).— केन्द्रीय सरकार, साधारण खंड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) की धारा 8 के अनुसरण में यह अधिसूचित करती है कि जहां भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) या दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) या भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) या उसके किन्हीं उपबंधों का कोई निर्देश तत्समय प्रवृत्त निम्नलिखित में किया जाता है-

(क) संसद् द्वारा बनाया गया अधिनियम; या

(ख) किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाया गया अधिनियम;

(ग) अध्यादेश;

(घ) संविधान के अनुच्छेद 240 के अधीन बनाए गए विनियम;

(ङ) राष्ट्रपति का आदेश;

(च) किसी अधिनियम के अधीन बनाए गए नियम, विनियम, किया गया आदेश या अधिसूचना, अध्यादेश या विनियम,

वहां ऐसा निर्देश क्रमश: भारतीय न्याय संहिता, 2023 (2023 का 45) (बीएनएस), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का 46) (बीएनएसएस) या भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 (2023 का 47) (बीएसए) के निर्देश के रूप में पढ़ा जाएगा और ऐसी विधि के तत्स्थानी उपबंधों का अर्थ तदनुसार लगाया जाएगा ।

[फा. सं. 13(12)/2024-वि.-1]

दिवाकर सिंह, अपर सचिव

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th July, 2024

S.O. 2790(E).—In pursuance of section 8 of the General Clauses Act, 1897 (10 of 1897), the Central Government hereby notifies that where any reference of the Indian Penal Code (45 of 1860), or the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) or the Indian Evidence Act, 1872 (1 of 1872 or any provisions thereof is made in any—

(a) Act made by Parliament; or

(b) Act made by the Legislature of any State;

(c) Ordinance;

(d) Regulations made under article 240 of the Constitution;

(e) President's order;

(f) rules, regulations, order or notification made under any Act, Ordinance or Regulation,

for the time being in force, such reference shall respectively be read as the reference of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (45 of 2023) (*BNS*), the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (46 of 2023) (*BNSS*) or the Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023 (47 of 2023) (*BSA*), and the corresponding provisions of such law shall be construed accordingly.

[F. No. 13(12)/2024-Leg.I]

DIWAKAR SINGH, Addl. Secy.

No. 9/9/2001-FOR/2011
Government of Goa,
Forest Department,
Secretariat, Porvorim.

Dated: 21/06/2011

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 32 of the Goa, Daman and Diu Preservation of Trees Act, 1984 (Act 6 of 1984), the Government of Goa, in the interest of general public, hereby extends the ban (read earliest Notification No. 8/10/83-FOR dated 11/09/1990) on felling of the following mangroves species until further orders:-

1. Rhizophora mucronata
2. Kandelia rheedii
3. Avicennia officinalis
4. Sonneratia alba
5. Ceriops tagal
6. Excoecaria agallocha
7. Rhizophora apiculata
8. Bruguiera gymnorrhiza
9. Avicennia marina
10. Sonnoratia Caseolaris
11. Aegiceras corniculatum
12. Acanthus ilicifolius
13. Derris heterophylla
14. Acrostichum aureum
15. Bruguiera parviflora
16. Lumnitzera racemosa

This supercedes the earlier notification No. 2-107-2000-FD/2506 dated 24/08/2000.

By Order and in the name of the
Governor of Goa,

(Maria J. R. Pires)
Under Secretary(Forests)

To,
The Director, Printing & Stationery, Panaji with a request to publish in the next issue of Government Gazette and send 5 copies of the Gazette to this Department.

Copy to:-
1. The Dy. Conservator of Forests, Research and Utilization, Margao for information.
2. Concerned file.
3. Guard file

Dy. Conservator of Forests (Planning & Statistics), Forest Deptt, Panaji w.r.t. his letter No. 2-107-93-II-FD/705 dated 16/5/2014.

Email 1870 21/08/24 Principal Chief Conservator Forest Dept Goa

Captive Elephant (Transfer or Transport) Rules, 2024 -reg.

From : projectelephant moefcc <projectelephant.moefcc@gmail.com> Wed, Aug 21, 2024 12:37 PM

Subject : Captive Elephant (Transfer or Transport) Rules, 2024 -reg. 2 attachments

To : wildlifeandhrapradesh@gmail.com, wildlifeap@gmail.com, cwlw-ar@nic.in, cwlwarunachal@gmail.com, pccfcwlw-arn@nic.in, pccfwildlife@gmail.com, pccfwlassam@gmail.com, pccf wl assam <pccf.wl.assam@gmail.com>, cwlw assam <cwlw.assam@gmail.com>, pccf wl <pccf.wl@assam.gov.in>, cwlwbihar@rediffmail.com, pccfbihar@gmail.com, cwlwbihar@gmail.com, cwlwcg@gmail.com, pccfwildlifecg@gmail.com, pccfwlhry@gmail.com, apccfwl@gmail.com, SHASHIKAR SAMANTA <pccf-wildlife@gov.in>, PRADEEPKUMAR PRADEEPKUMAR <pccfwljhk@jharkhandmail.gov.in>, pccfwljharkhand@gmail.com, pccfwl@gmail.com, CWW <cww.for@kerala.gov.in>, CWW <cww@forest.kerala.gov.in>, Principal Chief Conservator of Forest, WildLife,Nagpur Maharashtra Forest Department <pccfwlngp@mahaforest.gov.in>, cwlwmanipur@gmail.com, PCCF Wild Life HO Bhopal <pccfwl@mp.gov.in>, wildlifemegh@yahoo.com, nagacwlw@yahoo.co.in, nagaland forest <nagaland.forest@gmail.com>, pccfodisha@gmail.com, pccfwlodisha@gmail.com, cwlw raj <cwlw.raj@gmail.com>, pccf cwlw forest <pccf.cwlw.forest@rajasthan.gov.in>, apccf cwlw forest <apccf.cwlw.forest@rajasthan.gov.in>, cwlw wildlife3 <cwlw_wildlife3@yahoo.co.in>, chiefwildlife@gmail.com, pccftripura@gmail.com, cwlwua@yahoo.co.in, cwlwup@rediffmail.com, cwlwup@gmail.com, Debal Ray, IFS <pccfwl-wb@nic.in>, CWLW, West Bengal <pccfwloffice.fd-wb@bangla.gov.in>, wbwildlife@gmail.com, cwlwguj@gmail.com, apccfforestry@gmail.com, ccfgnctd@gmail.com, Conservator of Forests,Puducherry <cf.pon@nic.in>, Raman Kant Mishra <cwlw@punjab.gov.in>, cwlwpunjab@gmail.com, Deputy Conservator of Forests Head Quarter <dcfhq-forest.goa@nic.in>, Principal Chief Conservator Forest Dept Goa <pccf-fore.goa@gov.in>, pccfwl@and.nic.in, pccfwl and <pccfwl.and@nic.in>, PCCF Working Plan <pccfwp@mp.gov.in>, RAKESH MOHAN DOBRIYAL, IFS <prlccf_hf_tsfd@telangana.gov.in>

Cc : PCCF MP PCCF MP P C C F M P <pccfmp@mp.gov.in>, pccf raj forest <pccf.raj.forest@rajasthan.gov.in>, Shri Rajpal Singh, IFS <hoff-assam@gov.in>, Chiranjiv Choudhary, IFS <prlccf_hf_apfd@ap.gov.in>, PCCF Secretary <pccfnsecy-arn@nic.in>, CGMFP Federation Raipur <mfpfed.cg@nic.in>, pccf-forest goa <pccf-forest.goa@gov.in>, pccf-forest@gujarat.gov.in, Pankaj Goel <pccf-hry@nic.in>, prs-fee@karnataka.gov.in, secyforestfee@gmail.com, pccfkar@gmail.com, HoFF Kerala <pccf.for@kerala.gov.in>, PCCF Hoff Maharashtra Forest Department <pccfhoffngp@mahaforest.gov.in>, PCCF Manipur <pccf-mn@nic.in>, pccfmegh@gmail.com, pccfcomplex@gmail.com, Forest tnforest <tnforest@nic.in>, PCCF HOD <pccf-up@nic.in>, Niraj Singhal, IFS <pccfhoff-wb@nic.in>, pccf-tn@nic.in, pccfhod@gmail.com, pccfani@gmail.com, Dr. Avinash Maheshwarji Kanfade <hoff.tfd-tr@gov.in>, pccfmp@rediffmail.com, pccf-gj@nic.in, Ramesh Pandey <ramesh.pandey@nic.in>, DHEERAJ MITTAL <gj178.ifs@nic.in>, kumar.rajendra <kumar.rajendra@nic.in>, projectelephant moef <projectelephant.moef@gmail.com>

Office of the P.C.C.F
Inward No. 5360
Book No. 5124
Date 21/08/2024

Respected Madam/Sir,

Please find attached copy of the Office Memorandum regarding the subject cited above for your information and needful action please.

With regards,

Project Elephant,
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
6th Floor, Jal Block,
Indira Paryavaran Bhawan,
Jor Bagh Road,
New Delhi 110003.

OM for complinace of Transfer and Transport Rules 2024.pdf

F. No. 2-7/1998-PE (Vol.1)
Government of India/ भारत सरकार
Ministry of Environment, Forest & Climate Change/पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
(Project Tiger & Elephant Division / व्याघ्र एवं हाथी परियोजना प्रभाग)
****

Indira Paryavaran Bhawan,
Jor Bagh Road, New Delhi-110003.
Dated: 20th August, 2024

OFFICE MEMORANDUM

Sub:- Captive Elephant (Transfer or Transport) Rules, 2024 -reg.

Elephant has been listed as Schedule-I species under the Wildlife (protection) Act, 1972 according the highest degree of protection to both wild and in captivity. The Ministry on various occasions has received, representations and complaints regarding the illegal transfer and transport of elephants, sale and procurement of elephants. In order to address these concerns and regulate the movement of captive elephants within and between States in India, the Government of India has notified "Captive Elephant (Transfer or Transport) Rules, 2024" (copy of the rules is enclosed). In this regard, kind attention is drawn with regard to the provision of clause (7) Terms and Conditions, sub-clause (3) which mandates that "*No transfer of an elephant shall be permissible unless genetic profile of the elephant has been entered in the electronic monitoring application of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change*".

Hence, it is requested to take all necessary action to ensure the compliance of these rules while transfer or transport of elephant from one place to another.

Encls: as above.

Signed by
Rajendra Kumar
Date: 21-08-2024 10:25:22

(Dr. Rajendra Kumar)
Scientist 'C' (Project Elephant)
Email: kumar.rajendra@gov.in

The Principal Chief Conservator of Forests (WL) &
Chief Wildlife Warden,
All Elephant Range States/UTs.

Copy to: For information and necessary action.

- PCCF & HoFF, All Elephant Range States/UTs.
- PS to IGF (PT&E) & Director (Project Elephant), MoEF&CC.

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th March, 2024

G.S.R. 191(E).— In exercise of the powers conferred by clause (gviii) of sub- section (1) of Section 63 of the Wild Life (Protection) Act, 1972 (53 of 1972), the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

1. **Short title and commencement.** – (1) These rules may be called the Captive Elephant (Transfer or Transport) Rules, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definition .**- (1) In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) "Act" means the Wild Life (Protection) Act, 1972 (53 of 1972);

(b) "donor State" means a State from whose jurisdiction the elephant is going to be transferred;

(c) "elephant" means a captive elephant in respect of which an ownership certificate has been issued under Section 42 of the Act;

(d) "elephant assistant" means a person engaged to assist the Mahout;

(e) "Form" means form appended to these rules;

(f) "mahout" means the person who manages the elephant;

(g) "owner" means a person having a valid certificate of ownership for the elephant issued under section 42 of the Act;

(h) "recipient State" means a State in whose jurisdiction the transfer of elephant is going to be transferred;

(i) "veterinary practitioner" means a person registered with the Veterinary Council of India established under the Indian Veterinary Council Act, 1984 (52 of 1984);

(2) The words and expressions used and not defined in these rules but defined in the Act shall have the meaning respectively assigned to them in the Act.

3. **Application for Transfer of Elephant .**– An application for transfer of elephant shall be made in Form I to the officer not below the rank of Deputy Conservator of Forests having jurisdiction over the area where the elephant is registered.

4. **Inquiry by the Deputy Conservator of Forests.**-(1) On receipt of the application under rule 3, the Deputy Conservator of Forests shall:-

(a) obtain a certificate of a veterinary practitioner in Form II;

(b) conduct a detailed inquiry and physical verification of the facility where the elephant is presently housed and also the facility where the elephant is proposed to be housed in case the facility is located within his jurisdiction; and

(c) forward the application and report in Form III along with the report of veterinary practitioner within a period of fifteen days to the Chief Wild Life Warden.

5. **Transfer within the State.**-(1)The Chief Wild Life Warden after examination of reports may, within a period of seven days by an order in writing reject or permit the transfer of the elephant, if such elephant is proposed to be housed within the jurisdiction of the officer receiving the application under rule 3.

(2) The Chief Wild Life Warden shall forward the application and the reports received as per sub-rule (1)(c) of rule 4 to the officer not below the rank of Deputy Conservator of Forests having jurisdiction over the area where the elephant is proposed to be housed and is outside the jurisdiction of the officer receiving the application under rule 3, within a period of seven days.

(3) The concerned Deputy Conservator of Forests shall on receipt of the application and the reports in accordance with sub-rule (2) conduct a detailed inquiry and physical verification of the facility and submit report in Form III within a period of fifteen days to the Chief Wild Life Warden.

(4) The Chief Wild Life Warden after examination of the application and the reports may, within a period of seven days by an order in writing reject or permit the transfer.

6. **Transfer outside State.**- (1) The Chief Wild Life Warden of the donor State shall forward the application along with the reports received as per (c) of sub-rule (1) of rule 4 within a period of fifteen days to the Chief Wild Life Warden of the recipient State.

(2) The Chief Wild Life Warden of the recipient State shall within a period of seven days forward the application and the reports to the officer not below the rank of Deputy Conservator of Forests having jurisdiction over the area where the elephant is going to be housed.

(3) The concerned Deputy Conservator of Forests shall on receipt of the application and

accordance with sub-rule (2) conduct a detailed inquiry and physical verification of the facility and submit report within a period of fifteen days in Form III to the Chief Wild Life Warden.

(4) The Chief Wild Life Warden of the recipient State after receipt of the reports as per sub-rule (3) shall forward his recommendations to the Chief Wild Life Warden of the donor State in Form IV within a period of fifteen days.

(5) The Chief Wild Life Warden of the donor State after examination of the reports shall, within a period of seven days by an order in writing reject or permit the transfer.

(6) The Chief Wild Life Warden of the donor State shall intimate the order of rejection or permission of transfer to the Chief Wild Life Warden of the recipient State.

7. **Terms and Conditions for transfer.-** (1) The Chief Wild Life Warden shall permit the transfer where the ownership certificate in respect of the elephant proposed for transfer existed prior to coming into force of these rules except in case of elephant borne from such elephants.

(2) The transfer of the elephant may be permitted by the Chief Wild Life Warden, in case:-

(a) the owner is no longer in a position to maintain the elephant; or
(b) the elephant will have a better upkeep than in the present circumstances; or
(c) he deems it fit and proper in the circumstances of the case for better upkeep of the elephant.

(3) No transfer of an elephant shall be permissible unless genetic profile of the elephant has been entered in the electronic monitoring application of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change.

8. **Application for Transport of elephant .-** (1) An application for transport of an elephant shall be made in Form V to the officer not below the rank of the Deputy Conservator of Forests having jurisdiction over the area where the elephant is registered.

(2) The concerned Deputy Conservator of Forests shall, on receipt of the application obtain a report of a veterinary practitioner in Form II and submit his recommendations in Form III along with the report of veterinary practitioner within a period of fifteen days to the Chief Wild Life Warden.

(3) The Chief Wild Life Warden may, on receipt of the application and reports in accordance with sub-rule (2), issue a transport permit in Form VI or reject the application by an order in writing.

(4) The Chief Wild Life Warden shall forward a copy of the transport permit to:-

(a) the concerned Deputy Conservator of Forests within the state through whose jurisdiction the elephant is to be transported; and

(b) the concerned Chief Wild Life Warden through whose jurisdiction the elephant is to be transported.

9. **Conditions for transport.-** (1) The transport of the elephant in respect of which a transport permit has been issued shall be with the following conditions that:-

(a) the elephant shall be accompanied by a mahout and an elephant assistant;

(b) a health certificate from a veterinary practitioner to the effect that the elephant is fit for transport and is not showing any sign of musth or infectious or contagious disease, is obtained;

(c) the transport shall be carried out after the mandatory quarantine period as advised by the veterinary practitioner r is over, in case of contagious disease;

(d) the elephant shall be properly fed and given water before loading;

(e) necessary arrangements shall be made for providing food and water to the elephant en route;

(f) tranquilisers/sedatives shall be used to control nervous or temperamental elephants upon prescription by the veterinary practioner.

10. **Validity**.- (1) The transfer of the elephant shall be effected within a period not exceeding three months from the date of grant of permission.

(2) The validity of the transport permit shall not be more than one month.

(3) No extension of validity of permission for transfer or transport permit shall be granted.

11. **Appeal .-** (1) An applicant aggrieved by the refusal of the Chief Wild Life Warden may prefer an appeal to the administrative Head of the State Forest Department of the concerned State Government within a period of sixty days from the date of receipt of the orders of the Chief Wild Life Warden by a written statement sent through registered post justifying reasons for preferring an appeal.

(2) The State Government shall pass appropriate orders on the appeal within a period of thirty days of receipt of the appeal.

Form I
[See rule 3]

Form I Application for transfer of Elephants		
1.	Name of the applicant / owner	
2.	Permanent Address	
3.	Present Address	
4.	Date of acquisition of Elephant	
5.	Name of the present owner of Elephant	
6.	Address of the owner of the Elephant	
7.	Address of the housing facility of the Elephant	
8.	Name of the Elephant (if applicable)	
9.	Microchip number of the Elephant	
10.	Age and sex of the Elephant	
11.	Whether applying for transfer within or outside state	
12.	Place of transfer	From [name of the District, State] To [Name of the District, State]
13.	Address of the transferee housing facility of the Elephant	
14.	Purpose of transfer	
15.	Any other detail	

Undertaking

I .....[name of the applicant] Son or Daughter or Wife of .....[Father's name or Husband's Name] hereby declare that all the particulars furnished by me are true to the best of my knowledge and any detail furnished above, if found to be false, shall make my application liable for rejection.

I shall abide by all the conditions mentioned in the Captive Elephant (Transfer or Transport) Rules, 2024 and any other condition that may be imposed by the Chief Wild Life Warden.

Date:
Place:

Signature

Name of the Applicant:
Present Address of the Applicant:

List of enclosures:

1. Authorisation letter in case the applicant and owner are different
2. Copy of the present ownership certificate
3. Copy of the Aadhar Card/ Address proof of the present Owner/ Applicant
4. Registration Certificate/Certificate of incorporation in case of a Society/Company/Board etc.
5. Certificate of fitness of the Elephant from the veterinary doctor

Form II

[See sub-rules (1) (a) of Rule 4 and sub-rule (2) of rule 8]

Form II **Certificate by the Veterinary practitioner**		
1.	Date and Time of Examination	
2.	Name of the present owner of Elephant	
3.	Name of the Elephant (if applicable)	
4.	Microchip number of the Elephant	
5.	Age and sex of the Elephant	
6.	Address of the housing facility of the Elephant	
8.	Any other detail	
9.	Recommendations	
	Undertaking I, Dr....., registered as a veterinary practitioner under the Veterinary Council Act, 1984, examined the above described animal on (date)..... and certify that the animal is sound/ unsound in health. Place: Date: Signature: Name & Address: VCI Registration No. Email: Contact No:	

Form III

[See sub-rule (1)(c) of rule 4, sub-rule (3) of rule 5, sub-rule (3) of rule 6 and sub-rule (2) of rule 8]

Form III **Report of the Deputy Conservator of Forests**		
1.	Name and address of the Applicant	
2.	Name and address of the present owner of Elephant	
3.	Name of the Elephant (if applicable)	
4.	Microchip number of the Elephant	
5.	Age and sex of the Elephant	
6.	Address and GPS location of the housing facility of the Elephant	
7.	Address of the transferee housing facility of the Elephant along with name of Division and District	
8.	Date of Inspection by the Deputy Conservator of Forests having territorial jurisdiction over the area	
9.	Whether all the health check up of the elephant carried out regularly	
10.	Whether the elephant is fit	
11.	Any other detail	
12.	Recommendations	
	Date: Place: Signature Name of the Officer: Designation: To The Chief Wild Life Warden, Address.....	

Form IV
[See sub-rule (4) of rule 6]

	Form IV **Recommendations of the Chief Wild Life Warden of the recipient State**	
1.	Name and address of the Applicant	
2.	Name and address of the present owner of Elephant	
3.	Name of the Elephant (if applicable)	
4.	Microchip number of the Elephant	
5.	Age and sex of the Elephant	
6.	Name and address of the transferee	
7.	Address of the transferee housing facility of the Elephant along with name of Division and District	
8.	Date of Inspection (if carried out)	
9.	Recommendations	
	Date: Place: Signature Name of the Officer: Designation: To The Chief Wild Life Warden (Donor State), Address…..	

List of enclosures:
Recommendations of the Deputy Conservator of Forests having territorial jurisdiction over the area in recipient State in Form III.

Form V
[See sub-rule (1) of rule 8]

Form V **Application for transport of Elephant(s)**		
1.	Name of the Applicant / Owner	
2.	Permanent Address	
3.	Present Address	
4.	Date of acquisition of Elephant	
5.	Name of the present owner of Elephant	
6.	Address of the owner of the Elephant	
7.	Address of the housing facility of the Elephant	
8.	Name of the Elephant (if applicable)	
9.	Microchip number of the Elephant	
10.	Age and sex of the Elephant	
11.	Whether applying for transport within or outside State	
12.	Place of transport	From [name of the District, State] To [Name of the District, State]
13.	Purpose of transport	
14.	Proposed date of return to original housing facility (in case of temporary transportation)	
15.	Name and address of Mahout accompanying the Elephant	
16.	Name and address of Assistant accompanying the Elephant	
17.	Details of Mahout and Assistant at the place where the elephant is being transported	
18.	Any other detail	

Undertaking

I .....[name of the applicant] Son or Daughter or Wife of .....[Father's name or Husband's Name] hereby declare that all the particulars furnished by me are true to the best of my knowledge and any detail furnished above, if found to be false, shall make my application liable for rejection.

I shall abide by all the conditions mentioned in the Captive Elephant (Transfer or Transport) Rules, 2024 and any other condition that may be imposed by the Chief Wild Life Warden.

Date:
Place:

Signature

Name of the Applicant: Present Address of the Applicant:

List of enclosures:

1. Authorisation letter in case the applicant and owner are different.
2. Copy of the present ownership certificate.
3. Copy of the Aadhar Card/ Address proof of the present Owner/ Applicant.
4. Registration Certificate/Certificate of incorporation in case of a Society/Company/Board etc.
5. Certificate of fitness of the Elephant from the veterinary practitioner.
6. Copy of adhaar card of Mahout and Assistant.

Form VI
[See sub-rule (3) of rule 8]

Form VI
Transport Permit for Elephant issued by the Chief Wild Life Warden

1.	Name of the Applicant	
2.	Name of the present owner of Elephant	
3.	Name of the Elephant (if applicable)	
4.	Microchip number of the Elephant	
5.	Age and sex of the Elephant	
6.	Address of the housing facility of the Elephant	
7.	Transport permitted	a. From [date] to [date] b. From [name of District, State] To [name of District, State]
8.	Any other detail	
9.	Recommendations	

Conditions for transport:

1. The elephant for which a transport permit has been granted shall be accompanied by a mahout and an elephant assistant.
2. A health certificate from a veterinary doctor to the effect that the elephant is fit to travel by road or rail, as the case may be, and is not showing any sign of *musth*or infectious or contagious disease shall be obtained in;
3. The elephant shall be properly fed and given water before loading;
4. Necessary arrangements shall be made for feeding and watering the elephant on route;
5. Sedatives, if necessary, shall be used to control nervous or temperamental elephants only as prescribed by the veterinary practitioner.
6. Any other conditions (to be specified)

Date:
Place:

Signature

Name of the Officer:
Designation of Officer:

To,
The Name and Address of the Applicant

Copy to:
1. The Deputy Conservator of Forests having territorial jurisdiction over the area in which the elephant is registered.
2. The Deputy Conservator of Forests having territorial jurisdiction over the area through which the elephant is going to be transported.
3. The Chief Wild Life Wardens of all the states in case of inter-state transport.

[F. No. WL-1/2/2023-WL]

SUSHIL KUMAR AWASTHI, Addl. Director General of Forests and Director, Wild Life Preservation

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064